

मध्य प्रदेश में तेल निर्यातों के लिये सर्वेक्षण

2631. श्री नंदा चरण बीसिल : क्या डेट्रो-सिक्व और एलायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में तेल के निर्यात पाये जाने के आसार हैं, और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

डेट्रोसिक्व और एलायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू नवाब खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मध्यप्रदेश में भूगर्भीय मानचित्रण कार्य जो कि 1960-61 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ किया था मध्य प्रदेश के अधिक अनुकूल तटीय क्षेत्रों के स्तर विज्ञान और पूरा भूगोल के आकड़ों तैयार करने के लिए जारी रखा जा रहा है ।

पाँचवीं योजना में मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई परियोजनाएँ

2632. श्री नंदा चरण बीसिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की सूची किमती है जिनको पाँचवीं योजना में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुदान किया है परन्तु केंद्र सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है, और

(ख) उन परियोजनाओं को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र कर्) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की पाँचवीं योजना के अन्तर्गत की सभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने पाँचवीं योजना के लिए 10 बृहत् सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है, परन्तु उनको योजना में सम्मिलित करना इन की उपलब्धता, प्रत्येकीय

पहलुओं पर समझौते तथा परियोजनाओं की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा ।

Decision on representation from all India Railway Commercial Clerks' Association
Re: violation of Indian Railway Code

2633. SHRI CHANDRIKA PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6700 on the 10th April, 1973 regarding representation from All India Railway Commercial Clerks' Association regarding violation of Indian Railway Code and state :

(a) whether Government have since examined the representation from the All India Railway Commercial Clerks' Association;

(b) if so, the broad outlines of the decisions taken; and

(c) if not, the reasons therefor and the time likely to be taken by Government now?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes.

(b) A decision has since been taken not to recover the undercharges from the staff on the newspapers' parcels under dispute.

(c) Does not arise.

Charging Freight on perishable articles on Central Railway

2634. SHRI CHANDRIKA PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Questions No. 5041 on the 19th December, 1972 and USQ No. 3825 on 20-3-1973 regarding outstanding amount of undercharges on consignment and charging freight on perishable articles on Central Railways, respectively, and state:

(a) the reasons for which no action has been taken against the Chief Commercial Superintendent of Central Railway for recovery of undercharges;